AIDWA

मार्च, 2022
न्यूज़ लैटर

1. संपादकीय

2. 8 मार्च, 2022 - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आह्वाहन

- मरियम ढवले (राष्ट्रीय महासचिव, एडवा)

3. कर्नाटक हिजाब मुद्दे पर एडवा का वक्तव्य

4. सोशल मीडिया उपयोग दुरुपयोग के बीच जन्मती सूचना सभ्यता

- संध्या शैली (केंद्रीय कमेटी सदस्य, एडवा)

5. उप्र विधानसभा चुनाव (इस बार जनता के मुद्दों पर वोट)

- मधु गर्ग (केंद्रीय कमेटी सदस्य, एडवा)

6. उत्तराखंड विधान सभा – अबकी बार श्रीराम नही दिखे खेवनहार

- सुनीता पाण्डे (केंद्रीय कमेटी सदस्य, एडवा)

7. सियासत में गरीब महिलाओं का दाखला क्यों है इतना मुश्किल?

- नाइश हसन (सामाजिक कार्यकर्ता)

8. हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स का ऐतिहासिक आंदोलन जारी।

-सविता (राज्य महासचिव, जनवादी महिला समिति हरियाणा इकाई)

9. आओ प्यार करें

- नलिन रंजन सिंह (जलेस)

10. बम पनाहगाह में जन्मी नन्ही बच्ची के लिए

- मनजीत मानवी

सम्पादकीय

सुभाषिनी अली
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एडवा)

इस बार की सम्पादकीय उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के दौरान ही लिखने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 3 हफ्तों से कानपुर, इलाहाबाद के कोरांव, देवरिया के सलेमपुर और अब चंदौली के चकिया क्षेत्रों मे चुनाव प्रचार करने का मौका मिला। कानपुर कई सालों से भाजपा का गढ़ रहा है। यहाँ लोगों ने बिना उम्मीदवार के बारे मे सोचे, भाजपा को वोट देने का काम किया है। अक्सर यह जानते हुए भी कि जिसे वोट दे रहे हैं उसने कोई काम नहीं किया है लेकिन फिर भी उसीको वोट दिया गया है! शहर मे 199, 91 और फिर 2004 मे हुए ज़बरदस्त दंगों से पैदा गहरे धार्मिक ध्रुवीकरण इन जीतों का कारण था। इस बार, चीजें बहुत बदली हुई नज़र आयीं: बेकारी, गरीबी और योगी सरकार की हर क्षेत्र मे भारी असफलता बड़े मुद्दे बन गए और इनका असर भी चुनाव परिणामो मे देखने को मिलेगा।

कोरांव, सलेमपुर और चकिया वह इलाके हैं जहां भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने आदिवासी (कोल), दलित भूमिहीनों और तमाम गरीबों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। चकिया मे जनवादी महिला समिति की बहुत सक्रिय इकाई भी है और इस इलाके मे कोल और दलित महिलाएं, हाथ मे लाल झण्डा लिए, ज़मीन के लिए हुए जुझारू संघर्षों मे आगे रही हैं। इन्ही तीन सीटों पर जनवादी महिला समिति ने खुलकर सीपीआईएम के प्रत्याशियों को समर्थन देने का और बाकी सीटों पर जो भी दल भाजपा को हराने की स्थिति मे दिखाई देता है, उसको वोट देने का फैसला लिया है।

कोरांव, सलेमपुर और चकिया के कई गांवों मे जाने और वहाँ की महिलाओं के साथ बात-चीत करने का अवसर मिला। गरीबी, भूख और काम का अभाव अपनी उपस्थिति बड़े ही निर्मम तरीके से दर्ज कर चुके हैं। पहले से भी ज़्यादा। करोना काल मे लोगों की कमर ही टूट गयी है। योगी सरकार ने पूरी तरह से गरीबों की दुर्दशा को अपनी पीठ दिखाने का काम किया है। जिन गांवों मे हम गए, वह सरकार के झूठे प्रचार की सच्चाई को बयान कर रहे थे – उत्तर प्रदेश मे मिलने वाली बहुत ही कम 500/- की विधवा और वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही है। सलेमपुर मे एक विधवा मिली जो बेहरी-गूंगी भी है। उसके विचलित भाव को आपके सामने व्यक्त करना ही असंभव है। पूरे प्रदेश मे मनरेगा का काम बिलकुल बंद है। भूमिहीन परिवारों की महिलाओं ने बताया कि दूसरों के खेतों मे अब काम भी नहीं मिलता है क्योंकि मशीनों से काम हो रहा है। फिर भी, कुछ मजदूरी मिल जाती ही तो केवल 100/- रोज़ ही मिलते हैं। मुफ्त मे दिये जाने वाले राशन का भाजपा बहुत डंका पीट रही है लेकिन पूरे प्रदेश मे 5 किलो की जगह 4 किलो ही मिलते हैं और कई अति गरीब लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं। चुनाव के पहले, योगी सरकार ने नमक, तेल और चना भी दिया है (जो अब बंद हो गया है) लेकिन नमक मे प्लास्टिक जैसी चीज़ के होने के कारण उसका इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे हैं, चने मे अक्सर फुपूंद लगा होता है और पामोलिन के तेल की हींक से लोग परेशान हैं! इन महिलाओं के परिवार के जवान बेटे अधिकतर प्रवासी मजदूर हैं जो अक्सर दो साल मे एक ही बार घर आ पाते हैं। अब उनको मिलने वाला काम भी बहुत घट गया है और मजदूरी भी कम हो गयी है। एक मजदूर कोरांव मे मिला था जो केरला काम करने गया था

और लकड़ाऊन मे वहीं फंस गया था। उसने बताया कि वहाँ सरकार ने तमाम मजदूरों को भरपेट भोजन ही नहीं दिया बल्कि मालिक ने भी उनकी रहने की जगह खाली नहीं कारवाई। जब ट्रेने चलने लगीं, तो सरकार की तरफ से बस से उन्हे स्टेशन तक पहुंचाया गया, टिकट खरीद कर दिया गया और रास्ते का खाना भी उनको एक अच्छे बैग मे दिया गया।

ज़ाहिर है कि इन तमाम गांवों के बच्चों की पढ़ाई दो साल से बिलकुल बंद है। आनलाइन पढ़ाई इनके बस के बाहर हैं और योगी सरकार जो अब स्मार्ट फोन देने की बात कर रही है ने किसी प्रकार की मदद गरीब बच्चों की नहीं की। अधिकतर गरीब लड़कियों के बारे मे कहा जा रहा है कि उनकी पढ़ाई तो हमेशा के लिए छूट गयी है।

चकिया बनारस से लगा हुआ है। बनारस मे भी पिछले दिनों का भगवा जुनून कम देखने को मिल रहा है। इसीलिए, मोदी यहाँ हर महीने आ रहे हैं और, चुनाव से पहले, पूरे तीन दिन – देश के काम और यूक्रेन मे फंसे भातीय बच्चों को भूलकर – बनारस मे रहने वाले हैं। उन्हे उम्मीद है कि बाबा विश्वनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी पार्टी का बेड़ा पार लगा लेंगे।

उत्तर प्रदेश के गांवों की बदहाली निश्चित रूप से देश के कई हिस्सों की कहानी होगी। हमारे संगठन को ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं और पीड़ा को एक बार फिर अपने काम का केंद्र बिन्दु बनाने की आवश्यकता साफ दिखाई दे रही है।

पिछले दो महीनो के इस दौर मे, 5 राज्यों मे होने वाले विधान सभा के चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा हैं। इनका परिणाम अगर भाजपा के विपरीत जाता है तो हमारे संघर्षों को आगे बढ़ाने का रास्ता भी खुल जाएगा।

चुनाव के अलावा भी कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी हैं जिनका ज़िक्र इस अंक मे आपको मिलेगा। हरियाणा की स्कीम वर्कर्स का बहादुराना संघर्ष जो सरकार के आक्रमण, ठंड, बरसात और भूख के बावजूद जारी है हमारे संघर्षों के इतिहास मे एक मील का पत्थर है। यूक्रेन का युद्ध जो एक तरफ साम्राज्यवादी देशों के दोहरे, मक्कार चरित्र का पर्दाफाश करता है, वह दूसरी तरफ युद्ध मे होने वाली बरबादी का नया नमूना भी पेश कर रहा है।

आने वाले दिनों मे हमारी सरकार किस तरह के नए हमले करने जा रही है उसके भी स्पष्ट संकेत हैं: LIC के शेयर को बेचने की ज़बरदस्त तयारी हो रही है और खाना पकाने की गैस का दाम 105/- सिलिन्डर बढ़ा दिया गया है।

अंत मे एक ज़रूरी बात। उत्तर प्रदेश के चुनाव मे तमाम विपक्षी पार्टियां धूआधार प्रचार कर रही हैं लेकिन सांप्रदायिकता और मुसलमानों पर हो रहे तमाम हमलों पर खामोश हैं। केवल बामपंथियों मे इन सवालों पर बोलने की हिम्मत है। इस संदर्भ मे हम अपनी दिल्ली की बहनों को सलाम पेश करते हैं कि उन्होने सीपीआईएम के साथ मिलकर दिल्ली मे हुए दंगों के पीड़ितों को अपने दर्द को व्यक्त करने का मौका दिया और उनके समर्थन मे बड़ा धरना आयोजित किया।

8 मार्च, 2022 - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आह्वाहन

"शिक्षा और रोजगार हमारा अधिकार समान अधिकारों के लिए लड़ें, धर्मनिरपेक्षण भारत को पुनः प्राप्त करें"

मरियम ढवले (राष्ट्रीय महासचिव, एडवा)

8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 1910 से महिलाओं के लिए समानता, न्याय और हिंसा मुक्त जीवन के लिए संघर्ष को दोहराने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। क्लारा जेटकिन ने अगस्त 1910 में कोपेनहेगन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन में प्रस्ताव दिया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 से इस दिन को मनाना शुरू किया था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र का विषय "एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता" है। यह विषय दुनियां में महिलाओं और लड़कियों के योगदान को पहचानता है। जो सभी के लिए एक अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए लड़ रही हैं।

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन ने सीटूए डीवाईएफआई और एसएफआई के साथ संयुक्त रूप से 8 मार्च को मनाने का आह्वान किया है। नारा है "शिक्षा और रोजगार हमारा अधिकार" समान अधिकारों के लिए लड़ें धर्मनिरपेक्ष भारत को पुनः प्राप्त करें।

महामारी और मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा-आरएसएस सरकार की अत्यधिक अन्यायर्पूण स्पष्ट रूप से कारपोरेट समर्थक नीतियों ने महिलाओं के जीवन को दयनीय बना दिया है। इंडिया सप्लीमेंट 2022 की रिपोर्ट "असमानता मार डालती है" से पता चला है कि जब देश में 84 प्रतिशत परिवारों को जीवन और आजीविका के भारी नुकसान से पिछले एक वर्ष में अपनी आय में गिरावट का सामना करना पड़ा। जबकि भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई।

"विश्व असमानता रिपोर्ट 2022" में कहा गया है कि भारत बढ़ती गरीबी और "समृद्ध अभिजात वर्ग" के साथ दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शीर्ष 10 प्रतिशत और शीर्ष 1 प्रतिशत के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57 प्रतिशत और 22 प्रतिशत है। जबकि सबसे निचले 50 प्रतिशत की आमदनी का हिस्सा घटकर 13 प्रतिशत हो गया है। देश के निचले 50 प्रतिशत के पास लगभग कुछ भी नहीं है। शीर्ष 10 प्रतिशत के पास टोटल घरेलू संपत्ति का 65 प्रतिशत हिस्सा है और शीर्ष 1 प्रतिशत के पास भारत में टोटल घरेलू संपत्ति का 33 प्रतिशत हिस्सा है।

यह भारत में बढ़ती जेंडर असमानता को भी दर्शाता है। भारत में महिला श्रम की कुल आय में हिस्सेदारी 18 प्रतिशत के बराबर है जो दुनिया में सबसे कम है। मनरेगा और केंद्रीय योजनाओं के लिए सरकारी खर्च में कटौती से हाशिए पर पड़े वर्गों को पूरी तरह से गरीबी के कगार पर धकेल दिया जा रहा हैए जिससे उनके पास जीवित रहने का कोई साधन नहीं है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में दिखाया गया है कि भारत में दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में भूखे लोग हैं। इसका मतलब यह है कि करोड़ों महिलाओं और लड़कियों को उनके पोषण और खाद्य सुरक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

सभी आवश्यक सेवाओं के निजीकरण ने देखभाल करने जैसे अवैतनिक कार्य और महिलाओं के घरेलू श्रम का बोझ बढ़ा दिया है। योजना कर्मियों को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता देने की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। कार्यस्थल पर भेदभाव और यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धताए संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण संघर्षों के निरंतर मुद्दे हैं। नई शिक्षा नीति बच्चों के एक बड़े वर्ग को उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के लिए एक कुटिल साजिश है।

महिलाओं के लिए समान अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के मुद्दों को पूरजोर तरीके से उठाया जाना चाहिए क्योंकि इन आदर्शों के लिये मनुवादी भाजपा-आरएसएस सरकार एक बहुत बड़ा खतरा है। यह सरकार भारतीय संविधान को खत्म कर देने और उसकी जगह पर मनुस्मृति को लाने के लिये तुली हुयी है यह ध्यान में रखना चाहिये।

हम सभी को पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता और भेदभाव से मुक्त लैंगिक समानता वाली दुनिया के लिए लड़ने के अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। एक ऐसी दुनिया जो बहुरंगी, न्यायसंगत और समावेशी है। एक ऐसी दुनिया जहां एक दूसरे की विभिन्नता का सम्मान होता है और उस विभिन्नता का आनंद मनाया जाता है।

आइये हम सब मिलकर महिलाओं की समानता की ओरआगे बढें।

कर्नाटक हिजाब मुद्दे पर एडवा का वक्तव्य

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेन्स एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए) मुस्लिम छात्राओं के अधिकारों की रक्षा करने में कर्नाटक राज्य सरकार की विफलता की कड़ी निंदा करती है। हिजाब पहनने के कारण इन छात्रों को उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

यह चौंकाने वाली बात है कि राज्य सरकार मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के अधिकार की रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए लगातार हस्तक्षेप करने की बजाय इस मुद्दे को गंभीर स्वरुप लेते हुये देखती रही। बजाय हस्तक्षेप के राज्य सरकार ने "समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले" कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश फिर से जारी किया। सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 के 133 (2) को लागू किया, जिसमें कहा गया था कि छात्रों को कॉलेज विकास समिति या पूर्व-विश्वविद्यालय कॉलेजों के प्रशासनिक बोर्ड की अपीलीय समिति द्वारा चुनी गई पोशाक पहननी चाहिए, जो पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और यदि कोई वर्दी तय नहीं की गयी है , तो "समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने वाले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए"।

कर्नाटक में मुस्लिम छात्रायें हिजाब पहनती रही हैं और कक्षाओं में भाग लेती रही हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने और डराने-धमकाने के लिए इस विवाद को जानबूझकर हवा दी गई है। भगवा स्कार्फ पहने और जय श्री राम के नारे लगाने वाले आक्रामक युवा लड़कों की भीड़ सांप्रदायिक ताकतों के घिनौने एजेंडे को उजागर करती है। "सार्वजनिक वातावरण" को भगवा ब्रिगेड द्वारा छोड़े गए गुंडों द्वारा विकृत किया जा रहा है, न कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों द्वारा।

यह अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 21-ए के तहत शिक्षा के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। इसी तरह, अनुच्छेद 15(1) और 15(2) अनुमति नहीं देते हैं। जन्म स्थान, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान कहता है कि किसी को भी सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जाना चाहिए। अनुच्छेद 29(2) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है।

कर्नाटक में हाल के घटनाक्रमों के कारण, मुस्लिम छात्राओं को इन सभी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय उडिपी गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की पांच

छात्राओं द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुनवाई कर रहा है । जैसा कि हम सबका अनुभव है ; भाजपा और आरएसएस के नेतृत्व वाली भगवा ब्रिगेड ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सांप्रदायिक लामबंदी और नफरत की राजनीति का इस्तेमाल किया है। इसने कर्नाटक में छात्र समुदाय के बीच उनकी वार्षिक परीक्षाओं के ठीक पहले तनाव की एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है। राज्य सरकार को किसी भी नियम और कानून को मनमाने ढंग से नहीं बदलना चाहिए, जिससे शैक्षणिक वर्ष के अंत में छात्रों के लिए एक कष्टदायक स्थिति पैदा हो, जिससे उनकी पढ़ाई में व्यवधान हो और विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के शैक्षिक अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

एडवा ने कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। राज्य सरकार को मुस्लिम लड़कियों की सभी प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें कॉलेजों में उनकी कक्षाओं में शामिल होने में मदद करनी चाहिए। सभी मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने या न पहनने के बारे में आदेश जारी करने के स्थान पर अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

किसी भी तरह की सांप्रदायिक और कट्टरपंथी ताकतों को छात्र समुदाय को विभाजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और शैक्षणिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष माहौल को खराब करने से रोका जाना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे असामाजिक तत्वों से सख्ती से निबटा जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं और मंत्रियों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान देना बंद करना चाहिए।

एडवा सभी छात्रों से, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, एकजुट रहने और भगवा ब्रिगेड के नापाक मंसूबों को हराने की अपील करती है।

सोशल मीडिया उपयोग दुरुपयोग के बीच जन्मती सूचना सभ्यता

संध्या शैली
(केंद्रीय कमेटी सदस्य, एडवा)

दो दिन पहले - 12 फरवरी को - दुनियां ने उस महान वैज्ञानिक चार्ल्स डारविन की जयंती मनायी जिसने मानव के विकास की प्रक्रिया को समझ कर बताया था कि किस तरह दुनियां में प्राणियों की उत्पत्ति और विकास हुआ। इस विकास क्रम में दुनियां के अलग अलग हिस्सों में मानवता अलग अलग तरीके से विकसित हुयी है। यद्यपि सभ्यता का विकास मशीनी क्रांति और पूंजीवाद के विकास के साथ और अधिक तेजी के साथ हुआ और मानवीयता, मानवीय अधिकार, मानवीय स्वतंत्रता, जनतंत्र जैसे शब्द भी ईजाद हुये। लेकिन पूंजीवाद जब इन तमाम शब्दों को वास्तविकता में उतारने वाले समाजवाद की धमक से थर्राया और बाजार का मुनाफा कम होने लगा तो उसने समाज में व्याप्त पुरातनपंथी नस्लवादी विचारों का सहारा लेकर अलग अलग देशों में तानाशाह राष्टवादी आइकॉन बनाने मे मदद करनी शुरू कर दी। मुसोलिनी,हिटलर और जापान का तोजो बीसवीं सदी के पहले पचास सालों में पनपे ऐसे ही तानाशाह थे। इन्होने अपने अपने देशों में ऐसा माहौल पैदा किया जिससे लोग इन शब्दों का अपने अपने तरीके से मतलब निकाल कर आपसी मतभेदों में उलझे रहें दुनियां को एक भयानक युद्ध की त्रासदी झेलनी पड़ी और पूंजीवादी मुनाफा फिर बढने लगा।

बीसवीं सदी यानि आज की दुनियां में एक बार फिर से वही हालत पैदा हो गयी है। अलग अलग देशों ने अपने अपने "लोकप्रिय" (!) तानाशाह खड़े कर लिये हैं। अगर हम इतिहास पढ़ें और उनकी और इनकी तुलना करें तो पायेंगे कि ये वे सारे काम कर रहे हैं जो वे उस वक्त करते रहे। इतिहास को बदलने की साजिशें और लोगों के दिमागों को विषैला करने की साजिशें इसमें सबसे महत्वपूर्ण थीं और हैं। इटली,जर्मनी और जापान तीनों ही देशों मे तानाशाहों ने किताबों को जलाने का हुक्म फरमाया था क्योंकि किताबें दिमागों को साफ करती थीं। और इस वक्त किताबों को जलाने के साथ साथ लिखें हुये को बदलने की साजिश रची जा रही है। हिंदुस्तान इसका सबसे बड़ा और ज्वलंत उदाहरण है। इसके लिये उपयोग में लायी जा रही है "सोशल मीडिया" !!

सोशल मीडिया एक ऐसी दुधारी छुरी है जिसे जनता अपने फायदे में और तानाशाह अपने फायदे मे इस्तेमाल कर सकता है। यह सही है कि किताबों का कोई विकल्प नहीं। लेकिन डिजिटलाइजेशन की इस दुनियां में सोशल मीडिया के तानाशाह द्वारा इस्तेमाल करने को लेकर रोने के बजाये जनता को अपना सोशल मीडिया मजबूत करना होगा। हिटलर के गोयबल्सी प्रचारतंत्र ने जर्मनी में लोगों के दिमागों में यहूदियों के बारे में जो झूठ भरे वे उस वक्त जर्मनी की जनता के सिर पर चढ कर बोले और करीब 20 लाख यहूदियों की हत्या तमाम कंसंट्रेशन

केैंप बनाकर कर दी गयीं। आज हमारे यहां पर भी इस स्थिति को लाने की तेजी से कोशिश हो रही है क्योंकि अब बढती बेरोजगारी, भुखमरी और बदहाली से जनता को तानाशाही आर्थिक नीतियों की पहचान होने लगी है। सोशल मीडिया का उपयोग अब इसलिये भी जरूरी है क्योंकि जनता तक खबर पहुंचाने वाले तमाम मीडिया घराने आरएसएस नियंत्रित सरकार के दरबारी पूंजीपतियों के कब्जे में हैं और वे जनता तक खबरें नहीं विज्ञापन पहुंचा रहे हैं।

सोशल मीडिया का उपयोग वामपंथियों और जनांदोलनों को इसलिये भी करना चाहिये क्योंकि आज दुनियां के सबसे अधिक फेसबुक चलाने वाले 35 करोड़ हिंदुस्तान में हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में 93 करोड लोगों के पास इंटरनेट वाले मोबाइल फोन हैं। यदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मो के हिसाब से इन उपयोगकर्ताओं का विभाजन किया जाये तो सबसे अधिक 86 प्रतिशत यू ट्यूब देखते हैं,76 प्रतिशत फेसबुक और 75 प्रतिशत व्हाट्सअप का उपयोग करते हैं। इनमें भी यह समझना आसान है कि आज के हिटलरों और गोयबल्सों को जनता को पुस्तकें जलाने का आदेश देने की जरूरत क्यों नहीं है। इस दुधारी छुरी को जनता अपने तरीके से इस्तेमाल करना भी सीख रही है। वेबन्यूज चौनल, चुटीले और तानाशाह की असलियत दिखाने वाले खबरिया चैनल, पुष्पा जिज्जी, भगतराम, उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय युवा नेहा सिंह राठौर के युवाओं की चिंताओं और तकलीफों को उजागर करने वाले वीडियो के अलावा समय समय पर जो खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं उन्हे उसी वक्त वीडियो उतार कर यू ट्यूब डालने की युवाओं की पहल भी जारी है। इसका उपयोग तेज करना और इसी माध्यम के द्वारा जनता के दिमागों को विषैला करने के प्रयासों को मिटाना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ किताबों को पढने का एक नया अभियान भी इस देश के युवाओं को चलाना होगा क्योंकि किताबों का विकल्प व्हाट्सएप युनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है य व्हाटस अप युनिवर्सिटी जिस तरह का जहरीला प्रचार कर रही है उसके उदाहरण सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई एप हैं। यह बुल्लीबाई एप्प और सुल्ली डील्स का विषाक्त कूड़ा भी ला रही है, व्हाट्सएप्प यूनिवर्सिटी के जरिये नफरत, घृणा, अज्ञान और विवेकहीनता का प्रसार भी कर रही है। जहरीला उन्माद फैलाकर संभावनावान पीढ़ी का आज और आगामी कल बर्बाद भी कर रही है। बुल्लीवाई एप और सुल्ली डील्स इन दोनों घिनौने एप्प्स के मामले में अभी तक पकडे गए आरोपियों में उत्तराखंड की श्वेता सिंह सिर्फ 18 वर्ष की हैं। उत्तराखंड का ही मयंक रावत और बैंगलोर से पकड़ा गया बिहार का इंजीनियरिंग का छात्र विशाल कुमार झा दोनों 21 वर्ष के हैं। इस एप्प को बनाने वाले असम के एक इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ने वाले जिस छात्र नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है वह भी सिर्फ 21 वर्ष का युवा है। जिस ओंकारेश्वर ठाकुर को सुल्ली डील्स में धरा गया है उसकी उम्र भी सिर्फ 26 साल है। श्वेता सिंह तो खुद एक युवती हैं, जिनके बारे में खबर है कि हिरासत में लिए जाने के बाद भी उनके मन में कोई मलाल या प्रायश्चित का भाव नहीं है।

श्वेता सिंह और इन संभावनाओं से भरे तकनीकी योग्यता वाले युवाओं को इतना विषाक्त किसने बना दिया कि एक महिला होने के बावजूद वे महिलाओं की ही नीलामी करने और उनके बारे में अश्लीलता की हद तक बेहूदा प्रपंच रचने में जुट गयी ? क्या यह नयी सूचना सभ्यता का प्रतीक है? यह सूचना सभ्यता दरअसल उस गोयबल्सी प्रचार का नया अवतार हैै जिसने जर्मनी की जनता और वहां युवाओं के दिमागों को इतना विषैला बना दिया था कि वे अपने पड़ोसी, अपने मित्र, अपने प्रोफेसर यहूदी को जान लेने और कंसंटेशन कैंप मे भेज कर अमानवीय यातनायें देने के लिये तैयार हो गये थे। जेसे पूंजीवाद अपने मुनाफे को बढाने के लिये उस तरह की जनता को तैयार करता है वैसे ही फासिस्ट तानाशाह अपने शासन को चलाने के लिये उस शासन को लोकप्रिय समझने वाली जनता को तैयार करता है। इस लोकप्रियता के झूठे मकड़ी के जाले से निकलना और सचाई के उजाले में देश को ले जाना ही असली सूचना सभ्यता है।

उप्र विधानसभा चुनाव

इस बार जनता के मुद्दों पर वोट ..

मधु गर्ग
(केंद्रीय कमेटी सदस्य, एडवा)

2017 की तर्ज पर ही भारतीय जनता पार्टी इस भुलावे में थी कि इस बार के चुनाव में भी उनके द्वारा बोई गई नफ़रत की फ़सल लहलहायेगी, किंतु इस बार जनता ने ठान लिया है कि उसे अपने बुनियादी मुद्दों पर ही टिके रहना है। मंहगाई , बेरोज़गारी , कोरोना कुप्रबंधन , छुट्टा जानवर, आवास, खेती किसानी जैसे मुद्दों का योगी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।

योगी जब से आये हैं उन्होंने 'ठोंक दो', 'बुलडोजर चलेगा' जैसे फरमान जारी कर यह छवि बनाने की कोशिश की कि वह एक ऐसे कठोर मुख्यमंत्री हैं जिनके राज्य में माफिया डर के मारे बिलों में दुबक गये हैं। सबको पता है कि 'माफिया' का मतलब एक विशेष समुदाय के लोग हैं। सच्चाई यह है कि इस समय भाजपा में सबसे ज्यादा अपराधिक छवि के लोग हैं। इस सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही दर्जनों संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज हैं , जिसे उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके वापस करवा लिया है। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमे वापस लिये गये हैं और आज वे चुनाव के मैदान में हैं।

अपनी सरकार की सभी नाकामियों को छिपाने के लिए 'अयोध्या का राम मंदिर ' 'दीपोत्सव' जैसे जनता के पैसों से किये गये भव्य आयोजन' 'काशी कारीडोर' 'मथुरा' किसी का भी जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ध्रुवीकरण की साज़िश के तहत योगी एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते हुए कभी कहते हैं कि पहले की सरकारों में 'अब्बाजान सारा राशन खा जाते थे 'या फिर 80- 20 का फार्मूला निकालते हैं, किन्तु जनता इनकी नफ़रत की राजनीति को खूब समझ रही है। गुंडाराज से लेकर आतंकवाद का भय भी जनता पर असर नहीं डाल पा रहा है । ध्रुवीकरण और नफ़रत फैलाने की साजिशों को नाकाम देख भाजपा की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और अब मोदी से लेकर योगी और अमित शाह के बयान इन्हें स्वयं ही मज़ाक का पात्र बना रहे हैं।

दरअसल आज उप्र में जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, और वह अपने बुनियादी मुद्दों पर ही वोट कर रही है (रिपोर्ट लिखने तक मतदान के पांच चरण हो चुके हैं) उप्र के गांव गांव से भाजपा के नेता खदेड़े जा रहे हैं, इनकी रैलियों में सरकारी इंतजामों से प्रायोजित भीड़ लाई जा रही है और बौखलाहट में प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री और मुख्यमंत्री तक कभी गिड़गिड़ाते तो कभी धमकी देते नजर आ रहे हैं। भाजपा की खिसकती ज़मीन को बचाने में संघ कार्यकर्ता और प्रचारक घर घर जा रहे हैं , व्यापारियों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। वे मोदी को 'भगवान'

के अवतार के रूप में पेश कर रहे हैं और यह भ्रम बना रहे हैं कि मोदीजी के हाथों में ही राष्ट्र सुरक्षित है। किंतु नोटबंदी और जीएसटी की मार खाया व्यापारी वर्ग इस सरकार में फैले भ्रष्टाचार से तबाह हो चुका है। उनका कहना है कि खुले आम अब "गुलाबी नोटों" की घूस मांगी जाती है।

योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटती होर्डिंग्स पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च कर प्रदेश के हर कोने को पाट दिया है, किन्तु हकीकत बहुत बदसूरत है। योगी की उपलब्धियों में मुफ्त राशन वितरण का बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है, किन्तु सबको पता है कि यह चुनावी लालीपॉप है, जो मार्च के बाद बंद हो जायेगा। जनता एक ओर मुफ्त राशन में मिलने वाले घटिया अनाज, नमक, व तेल से असंतुष्ट है, और दूसरी ओर आसमान छूती मंहगाई ने जरूरी चीजों की उपलब्धता को उसकी पहुंच से बहुत दूर कर दिया है । 200 रुपये लीटर सरसों का तेल, दाल और सब्जियां (विशेषकर शहरी गरीबों के लिए) खरीदना उसके लिए दूर की कौड़ी हो गया है। गैस सिलिंडरों पर जंग लग रही है। मोदी की उज्जवला योजना के विज्ञापन महिलाओं को मुंह चिढ़ा रहे हैं। गरीब बस्तियों और ग्रामीण इलाकों में महिलाएं एक स्वर में मंहगाई की शिकायत कर रही हैं. उधर मोदी योगी भ्रम पाले बैठे हैं कि उनकी सरकार का नमक खाकर उनके साथ जनता नमक हलाली नहीं करेगी। सच्चाई यह है कि जनता को रोज़गार चाहिए और मंहगाई पर लगाम, जिससे उसकी जेब में पैसा आये तो वह स्वयं बाजार से जरूरत का सामान ले सके।

योगी अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बहुत इतराते हैं जिसे एन सी आर बी के आंकड़े झुठला चुके हैं। जहां तक महिला सुरक्षा का प्रश्न है तो पूरे देश ने 'उन्नाव' व 'हाथरस' देखा है। योगी राममंदिर के निर्माण को अपनी एक और बड़ी उपलब्धि बताते हैं, वैसे इसकी हवा मंहगाई और बेरोज़गारी ने निकाल दी है। अयोध्या की सड़कों और गलियों में छोटी छोटी दुकानें चलाने वाले दुकानदारों पर तथाकथित विकास की तलवार लटकी हुई है , वे भव्य काशी कारीडोर के नाम पर बनारस की गलियों में सैकड़ों वर्षों से चलती हुई दुकानों का हश्र देख चुके हैं। अयोध्या के ग्रामीण इलाकों में बेसहारा जनता जानवरों से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि इन जानवरों को ही ' जोगी जी ' कहने लगी है। रात दिन जानवरों से खेत बचाती जनता पर मुफ्त राशन का भी कोई असर नहीं क्योंकि उनका कहना है कि कि जितना राशन मिलता है उससे ज्यादा तो फसल जानवर चट कर जाते हैं। एक और उपलब्धि, जिसकी बहुत जोर शोर से चर्चा की जा रही है वह है गांवों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना, किंतु शौचालयों की जर्जर दशा ने इस दावे को भी धराशाई कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में मीटिंग के दौरान महिलाओं ने बताया कि शौचालय निर्माण के लिए प्रधान के खाते में 12000 रुपए आते हैं जिसको बनाने का ठेका भी प्रधान ही ले लेता है। एक तो इतनी कम राशि में शौचालय बनना बहुत मुश्किल है, और फिर प्रधान भी अपनी कमाई के लिए घटिया श्रेणी का सामान लगाता है। गांवों में अधिकांश शौचालय कागजों पर हैं और जो हैं भी वे इतने जर्जर और टूटी फूटी हालत में हैं कि भूसे के

बोरे या कंडे रखने के काम आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा एक बड़ा मुद्दा है जिसमें काम लगभग बंद है। मनरेगा में मजदूरी का बकाया एक आम शिक़ायत है।

कोरोनाकाल में उप्र की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। केरल को उप्र की स्वास्थ्य व्यवस्था देखने का न्योता देने वाले योगी के शासनकाल में जिस प्रकार की बदइंतजामी देखने को मिली है उसे जनता आसानी से नहीं भूल पायेगी। कोरोना की पहली लहर में जहां पलायन कर आये मजदूरों की त्रासदी थी, वहीं दूसरी लहर में अस्पतालों में बेड व आक्सीजन की कमी ने मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया था। सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी थी। ग्रामीण इलाकों में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था झोलाछाप डाक्टरों के हवाले थी। शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे थे तथा अंतिम संस्कार के लिए टोकन बंट रहे थे। कोरोना में मृतक आश्रित परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान की घोषणा भी अभी कागजों पर ही है। उप्र की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल हाल में आये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने भी खोल दी है, जिसके एक आंकड़े के अनुसार उप्र में कुपोषित बच्चों की संख्या अफ्रीका के गरीब देश सूडान से भी ज्यादा ख़राब है। उप्र में स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है, किन्तु योगी सरकार का ध्यान मंदिरों, मूर्तियों व गऊ रक्षा पर ज्यादा है, जिससे जनता अब ऊब चुकी है।

एक ओर स्वास्थ्य का मुद्दा और दूसरी ओर शिक्षा से वंचित बच्चे, गरीब परिवारों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आन लाइन पढ़ाई ने गरीब बच्चों और संपन्न बच्चों के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर दिया है, किन्तु सरकार के लिए यह कोई मुद्दा नहीं है। आवास योजना व पेंशन, दलाली तथा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं हैं ,और अब वे होर्डिंग्स या कागजों पर ही हैं। हर बस्ती और गांवों में बूढ़ी और विधवा महिलाओं की यह मुख्य शिक़ायत होती है कि पहले पेंशन आती थी जो जाने क्यों कट गई है। युवाओं के बीच रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, उसे मंदिर मस्जिद में कोई रुचि नहीं है इस अभियान में जनवादी महिला समिति भी शामिल है.

इन बुनियादी मुद्दों पर ही उत्तर प्रदेश में सीपीएम तीन विधान सभा सीटों – सलेमपुर, कोरांव एवं चकिया में चुनाव लड़ रही है. गाँव गाँव में जनता के मुद्दों पर मीटिंग व प्रचार हो रहा है, जिसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है.

भाजपा के सारे पैंतरे फेल हो चुके हैं। जनता अपने बुनियादी मुद्दों की बात कर रही है जिससे एक उम्मीद जग रही है। दरअसल अब ध्रुवीकरण लूटने वालों और लुटने वालों के बीच है तो निश्चित रूप से लुटने वाले ही जीतेंगे।

उत्तराखंड विधान सभा –
अबकी बार श्रीराम नही दिखे खेवनहार

सुनीता पाण्डे
(केंद्रीय कमेटी सदस्य, एडवा)

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में राज्य विशेषकर पर्वतीय अंचल की भौगोलिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण खुद को मुख्यधारा से जोड़ने का यहॉ की जनता, को लम्बा ऐतिहासिक संघर्ष रहा है, जिसमें जल, जगंल जमीन से लेकर बढ़ते पलायन, उजड़ती, खेती बेरोजगारी अहम मुद्दे रहे हैं। चाहे पर्यावरण से जुडा चिपको आन्दोलन हो या नशे के खिलाफ आन्दोलन महिलायें अग्रिम पंक्ति मे ंखड़ी रही है।

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद भाजपा और कांग्रेस की आवत-जावत सरकारों ने जिन लुभावने वादों के साथ अब तक भोली-भाली जनता के बोट बटोरे है वो सब कोरे वादे साबित हुये हैं, ना ही राज्य के नीति नियोजन में समुदायों की भागेदारी के प्रयास रहे हैं ना ही
ऐसा कोई ब्लू प्रिंट अब तक तैयार हो पाया है जिसके आधार पर उत्तराखण्ड की दशा और दिशा तय हो।

अवैज्ञानिक तरीको से प्राकृतिक संसाधनों का बेरोकटोक दोहन, बड़े-बड़े बाधों का निर्माण, नग्न होते जंगल, अनियन्त्रित निर्माणों को अब तक राज्य का विकास कहा जाता रहा है जिसके चलते पिछले कुछ वर्षो से राज्य मे लगातार तेजी से आ रही बाढ़ों, भूस्खलन, भूकम्पों ने पहाड़ के शान्त जीवन में भूचाल ला दिया है। इन भीषण आपदाओं से उजड़ते खेत खलिहान ध्वस्त होते आवास, बेघर हुवे परिवार और जीवन जीने की असुरक्षा के बीच जिन्दगी जीते पीड़ित परिवारों के मुआवजे, पुर्नवास, रोजी रोटी के सवाल आज भी मुंह बायें खड़े है। जिन्हें पूरा करने में डबल इंजन की भाजपा सरकार असफल रही है

इन परिस्थितियों में वर्तमान में भाजपा सरकार "फिर से एक मौका और दो" की अपील 2022 के विधान सभा चुनाव में करती नजर आयी चुनाव से ठीक पहले बैठाई धर्म संसद की अवैध कार्यवाही पर वह एक तरफ कठघरे में खड़ी है तो भी इसी बहाने आर0एस0एस0 के धार्मिक उन्माद फैलाने के एजेण्डें का होम वर्क पूरा कर चुकी थी इस चुनावी समर में भगवान राम खेवनहार की भूमिका में नही दिखे बल्कि मजहबी दूरियां बनाने और हिन्दू धर्म को खतरे में दिखाकर मतदाता के बीच असुरक्षा का भाव पैदा करने के बीच मुहिम चलायी गयी जिसके रक्षक स्थानीय प्रतिनिधि न होकर सीधे पी0एम0 मोदी को माना गया।

कमर तोड़ मंहगाई कोविड महामारी के चलते घर लौटे प्रवासी परिवारों के आजिविका के सवाल, बिजली की कीमतों में वृद्धि राशन कार्डो के पात्रता चयन में धांधली, योजना की लाभों से वंचित परिवार, महंगी शिक्षा, बदतर स्वास्थ्य सेवाऐं, भारी बारिश व जंगली जानवरों के हमलो से हुये भारी जानमाल के नुकसान की भरपाई, महिलाओं, बच्चियों के साथ बढ़ती यौन हिंशाऐ, एकल

विधवा परित्यक्ता महिलाओं के सवाल, महिला कृषक के सवाल, बजट आवंटन में महिलाओं की अनदेखी, महिला हितों की अनदेखी, बदत्तर सड़क व्यवस्था, सड़कों से गॉव का जुड़ाव, युवाओं के सवाल, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे इस चुनाव के रहे लेकिन कोविड गाइड लाइन के चलते घर-घर जाकर हुये प्रचार में जन प्रतिनिधियों ने क्या वायदे किये और मतदाता उन्हें कितना जबावदेह बना पायें ये तो आगामी 10 मार्च को आने वाले चुनाव के परिणाम ही बताएंगें इन चुनावों के ठीक पहले बैठी धर्म संसद का एजेण्डा कि यदि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी तो हिन्दू धर्म खतरे में आ जायेगा की कानाफूसी चुनाव के दौरान नजर आयी जिसने जनता के मुख्य मुद्दों को गौड़ बना दिया। राज्य में वामपंथी पार्टियों का गठबंधन भी चुनाव मैदान में था जिन्होंने जन सरोकार से मुद्दों को लोगों के बीच उतारा जिसमें कुछ इलाकों में वह जनता का विश्वास जीतने में कामयाब दिखे।

प्रजातन्त्र में जहॉ मतदाता को जागरूक नागरिक मानकर जनता जनार्दन की राय को सर्वोपरी रखा गया है ऐसे में मूलभूत सवैधानिक अधिकारों का मंथन कर अपने हक हासिल करने के लिए प्रत्याशियों को जबाव देह और जिम्मेदार बनाने का काम आम नागरिक को ही करना पड़ता है लेकिन आते जाते चुनाव में मतदान सिर्फ ऑख मूदकर वोट देने का त्यौहार भर रह गया है जिसका परिणाम राज्य में हुआ 62.5 प्रतिशत मतदान रहा।

उत्तराखण्ड राज्य में जहॉ बुजुर्ग युवा और महिला आवादी किसी भी प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करने में अहम भूमिका निभाती है, महिलाऐं जो कि राज्य की आधी आवादी है वर्ष 2017 के चुनाव में पुरूष मतदाता से ज्यादा महिला मतदाता का प्रतिशत रहा है जो इस बार के चुनाव में भी देखने को मिला। तमाम राजनैतिक पार्टियां अपनी चुनावी घोषणा पत्रों में बड़े-बड़ें दावों से विभिन्न वर्गों को रिझानें में लगी रही लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है पहाड़ की चोटियों तक चढ़ जाने तक साहस रखने वाली महिलाओं की क्षमता किसी से छिपी नही है जिन्हें चुनावों में तो एक बड़े वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है लेकिन महिला केन्द्रित नीति नियोजन की दरकार आज भी अहम मुद्दा है। पंचायतों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के बावजूद विधान सभा में मात्र 7.1 प्रतिशत की महिला भागीदारी का सोचने विषय है जो वर्षो से लम्बित पड़े महिला आरक्षण के बिल के पास हुए बिना संभव नही दिखायी देता।

बेतहाशा शराब और धन वर्षा के कारण जनता के अहम मुद्दों से मतदाताओं का ध्यान भटकाने का सिलसिला पूरे चुनाव में दिखाई दिया जिसमें राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनता को पैसा बाटतें स्टिंग आपरेशन में दिखाई दिये। चुनाव आयोग सरसरे तौर पर अपनी भूमिका निभाते नजर आया।

यूं तो परम्परागत तरीकों से चुनाव का सिलसिला जारी रहेगा, गरीब कमजोर मध्यम वर्ग अपने सवालों में जूझता रहेगा और पहाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली महिला का ईधन, चारा, पानी की व्यवस्था, खेती पशुपालन बच्चों की देखरेख और घर का चूल्हा जलने की असुरक्षा के बीच संघर्ष भी सतत जारी रहेगा।

सियासत में गरीब महिलाओं का दाखला क्यों है इतना मुश्किल?

नाइश हसन
सामाजिक कार्यकर्ता

गुजरे सालों में कई ऐसे आंदोलन चले जिनका नेतृत्व महिलाओं ने संभाला। शबरी माला आंदोलन, हैप्पी टू ब्लीड आंदोलन, तीन तलाक आंदोलन, मी टू आंदोलन, एनआरसी आंदोलन, आदि कुछ बड़े आंदोलन रहे देश में जिनमें महिलाएं काफी मुखर होकर सामने आई। किसान आंदोलन में भी महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन आंदोलनों के नतीजे के तौर पर देखें तो पता चलता है कि महिलाएं सियासत के मामले में अब काफी जागरूक नजर आ रही है। वो बाकायदा अपने सवालों पर बहस भी करती है। अब वो अपने पतियों के कहने पर वोट नही ड़ाल रहीं। एनआरसी विरोधी आंदोलन से उभरी महिलाएं तो न सिर्फ अपना प्रत्याशी चुनने बल्कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। उज्मा परवीन का यहां तक कहना है कि अगर कोई पार्टी उन्हें टिकट नही देती तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहेंगी। इसी तरह रानी, इरम, सुनीता, आदि महिलाएं सामने आई जो चुनाव लड़ने के लिए खुद को तैयार कर चुकी है। ये एक अच्छा संकेत है, आधी आबादी का नजरिया सियासत के प्रति अब मुख्तलिफ हो गया है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा होना ही चाहिए।

इसी के साथ ये बात भी काबिले गौर है कि महिलाओं का वोट ड़ालने का प्रतिशत भी गुजरे सालों में बढा है। इसी बात को समझते हुए सभी दल महिलाओं को अपने-अपने तरीके से प्रलोभन देने की केाशिश कर रहे है। अगर हम 2007 से अब तक गौर करें तो पाते है कि महिला मतदाताओं का प्रतिशत हर चुनाव में बढा है। उत्तर प्रदेश के 2007 के विधानसभा चुनाव में 18 प्रतिशत महिला मतदान बढा, 2012 के विधान सभा चुनाव में 58.68 प्रतिशत पुरूष और 60.28 प्रतिशत महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इसी तरह 2017 के विधान सभा चुनाव में 59.15 प्रतिशत पुरूष और 63.31 प्रतिशत महिलाओं ने वोट किया था। तजर्बेकार बताते है कि इस बार भी इस प्रतिशत के बढने की उम्मीद है। प्रदेश में तकरीबन 7 करोड़ महिला वोटर है। इसके साथ ही प्रदेश में 8,853 थर्ड जेंडर मतदाता है।

महिलाओं से बात करने पर ये मालुम हुआ कि इस चुनाव में उनका मुख्य मुद्दा रोजगार, महिला सुरक्षा,करोना के बाद बढी मंहगाई है। बातचीत में कइयों की जबान पर हाथरस और उन्नाव बलात्कार कांड अभी भी ताजा है। कानून व्यवस्था की खस्ताहाल स्थिति को भी महिलाएं अपना अहम मुद्दा मानती है, उनका कहना है कि गंभीर से गंभीर घटनाओं में भी पुलिस प्रथम सूचना दर्ज करने और कार्यवाही करने से कतराती है।

2017 के चुनाव को देखें तो तकरीबन 41 प्रतिशत महिलाओं ने भाजपा को वोट किया था, उन्हें भाजपा का साइलेंट वोटर कहा जाता रहा है। भाजपा ने भी पिछली सरकार में महिलाओं पर

बढी हिंसा को मुख्य मुद्दा बनाया था, और अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 में महिलाओं से कई बड़े वादे किए थे, जैसे कि उनका पहला वादा था कि महिला उत्पीडन के मामलों के लिए वह 1000 महिला अफसरों का विशेष जांच विभाग महिला हिंसा के मामलों में और 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बानाएंगे, इसके साथ ही वादा ये भी था कि हर जिले में तीन महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, लेकिन वक्त गुजर गया और ये वादे उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में ही बंद रह गए।

इस दौरान जो नजर आया वो ये था कि महिला शक्ति मिशन, गुंडा दमन दल, ऑपरेशन मजनू, ऑपरेशन रोमियो जैसे कुछ टाइम बांउड गैर-गंभीर अभियान तो चले, लेकिन बेअसर ही रहे, नेश्नल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2021 बताती है कि महिलाओं के खिलाफ़ मामलों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। राष्ट्रीय महिला आयोग में 2021 में कुल शिकायतें 30,864 दर्ज की गईं जिनमें 15,828 शिकायतें सिर्फ उत्तर प्रदेश से थी।

हमने देखा कि एक तरफ महिला की बदहाल स्थिति में कोई सुधार आता इन 5 सालों में नजर नही आया, दूसरी तरफ महिलाएं उत्साहित है चुनाव में अपना मनपनसंद प्रत्याशी चुनने और स्वयं चुनाव लड़ने में। लेकिन गुजरे सालों में जिस तरह महिलाओं के मुद्दे अनदेखे किए गए, तामाम पित्रसत्तात्मक ताकतें औरतों के खिलाफ हावी दिखी ऐसे में क्या गरीब महिला का सियासत में जगह बना पाने का ख्वाब पूरा हो सकता है?

ये नारा अच्छा है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उत्साह भरता है महिलाओं में, लेकिन वो महिलाओं की राजनीति में राह आसान नही बना पाता। क्या वजह है कि गरीब महिलाओं के बीच से राजनीतिक नेत्रित्व उभर नही पाता? ये भी पड़ताल का विषय है। इसकी तह में कई बुनियादी सवाल है जो खास कर गरीब महिलाओं को हाशिए पर ढकेल देते है। 2021 की नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट बताती है कि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की 37.79 प्रतिशत आबादी गरीब है। ऐसे राज्य में क्या महिलाएं जिनकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं है वो मुख्य धारा की राजनीति कर पाएंगी। इसे और समझने के लिए हमें चुनाव में खर्च हूई रकम पर भी नजर ड़ालनी होगी।

2022 में होने वाले चुनाव में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा को 28 लाख से बढाकर 40 लाख कर दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट बताती है कि चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर दावेदारी करने वोल 615 प्रत्याशियों में 280 करोड़पति है। आम आदमी पार्टी के 52 प्रत्याशियों में 22 करोड़पति है। प्रत्याशियों की औसत सम्पत्ति 3.72 करोड़ रूपये है। प्रदेश में मौजूदा 396 विधायकों (7 सीटें रिक्त है) में से 313 करोड़पति हैं, उनकी औसतन सम्पत्ति 5.85 करोड़ रूपये है।

एक निजी शोध संस्थान सेंटर फॉर मीड़िया स्टड़ीज ने 2017 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होने विधानसभा चुनावों से पहले और बाद में किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक बताया था कि एक वोट पर औसतन 750 रूपये खर्च किया गया था, जो देश में सर्वाधिक था। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने एक वोट पर औसतन 5,500 रूपये खर्च किए थे। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रानिक माध्यमों के जरिए प्रचार में खर्च की रकम 6 से 9 सौ करोड़ तक थी। चुनाव के दौरान 200 करोड़ रूपये पकडे भी गए थे। संस्था ने अपने सर्वेक्षण के अनुसार अनुमान लगाया कि मतदाताओं को वोट के बदले 1000 करोड़ नकद भी बांटे गए थे। एडीआर ने प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा दिए गए हलफनामें की भी पड़ताल की तो पाया कि बुंदेलखंड से निर्वाचित होने वाले विधायकों ने 2017 में 16.07 लाख, पश्चिमी यूपी से जीत दर्ज करने वाले विधायकों ने औसतन 15.6 लाख, पूर्वांचल से 11. 87 लाख, मध्यांचल से 12.30 लाख और रूहेलखंड से 11.39 लाख रूपये खर्च दिखाया था, यह भी किसी से छिपा नही है कि चुनाव के दौरान जो प्रत्याशी खर्च दिखाते है वह वास्तविकता से बहुत कम होता है।

ऐसे वातावरण में जब महिलाओं को दोएम दर्जे का नागरिक बनाने और उसे घरों की तरफ ढकेल देने की कवायद में किसी भी प्रकार कमी नही आ रही, प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप ने कमजोर हों, ग्रामीण क्षेत्र में न रोजगार हो न शिक्षा हो, ऐसे में चुनाव खर्च को देखते हुए करोड़पति प्रत्याशियों के सामने इतना पैसा जुटा पाना एक गरीब पिछडी महिला के लिए मुश्किल ही नही नामुमकिन सा है। वह राजनीति में जोर आजमाते तमाम धनपशुओं से कैसे मुकाबला कर पाएगी। खास कर मुस्लिम, दलित और आदिवासी महिला जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ों में भी आखरी पायदान पर खड़ी है उसके लिए तो नेतृत्व कर पाना अभी ख्वाब जैसा ही है।

मौजूदा सरकार महिला हितैषी होने का बहुत दिखावा करती रही, तीन तलाक पर बहुत सीनाजनी करती रही, लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी भी महिला को मुख्य धारा में जगह दिलाने के लिए जमीन पर सरकार ने कोई ऐसा काम ही नही किया, अगर सरकार महिलाओं के सवाल पर संजीदा होती तो बहुमत की सरकार कम से कम महिला आरक्षण बिल तो पास करा ही सकती थी, लेकिन ऐसा भी हो न सका। इसी लिए सियासत में कोई मुकाम पाती केवल वही महिलाएं दिखती हैं जो राजनीतिक परिवारों की विरासत संभाल रही है। बाकी के लिए सियासत एक सपना ही है।

सवाल यह है कि आधी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिसमें उत्साह है, कुछ करने की क्षमता भी है वह अपनी सियासी भागीदारी कैसे बढाए, उसे पर्याप्त अवसर कैसे मिले, यह बड़ा प्रश्न है। यह बहुत मुनासिब वक्त था जब संसद में 33ः महिला आरक्षण बिल जो पिछले 25 वर्षो से लंबित है उसे पास कर दिया गया होता, तो निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या राजतीति में बढ जाती जो भारत के लोकतंत्र को गौरवांन्वित भी करती।

हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स का ऐतिहासिक आंदोलन जारी।

-सविता

(राज्य महासचिव, जनवादी महिला समिति हरियाणा इकाई)

हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स 8 दिसंबर 2021 से हड़ताल पर है और 14 फरवरी से हरियाणा के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र करनाल में राज्यस्तरीय रैली के बाद दिन रात का महापड़ाव डाला हुआ है। जिला स्तर पर भी महिलाएं लगातार धरना पर बैठी है और 25 26 फरवरी को हरियाणा के सभी भाजपा विधायकों के कार्यालयों पर रात्रि पड़ाव भी डाला है। 3 मार्च को हरियाणा विधानसभा घेराव के लिए चंडीगढ़ कूच का आह्वान किया गया है जिसे कुचलने के लिए सरकार एडी चोटी का जोर लगा रही है। वर्कर्स, हेल्पर्स को रास्तों में रोका जा रहा है, घरों में नजरबंद किया जा रहा है, बसों और अन्य साधनों को इंपाउंड किया जा रहा है, ड्राइवरों को धमकाया जा रहा है, रोडवेज की बसों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ना चढ़ने देने की एडवाइजरी जारी की गई है। परंतु सरकार के इस दमन चक्र और उत्पीड़न के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जहां उन्हें रोका जा रहा है वहीं रुक कर प्रदर्शन कर रही हैं। जो प्रदर्शन पहले केवल चंडीगढ़ में होना था, अब वह हरियाणा के विभिन्न जिलों में और स्थानीय इलाकों में हो रहा है।

भाजपा सरकार शुरू से ही इस आंदोलन के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपनाए हुए हैं। राज्य भर में 400 से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, दर्जनों को टर्मिनेशन के नोटिस जारी हो रहे हैं सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं परंतु महिलाएं मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों के साथ आंदोलन में जुटी हुई हैं।

इस आंदोलन ने मनुवादी भाजपा सरकार की महिला विरोधी मानसिकता और पितृसत्ता के क्रूर चेहरे को उघाड़ कर रख दिया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को ना केवल विभाग और सरकार से बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। नौकरी जाने का डर, 3 महीने से वेतन ना मिलना, आंदोलन में आने-जाने के खर्चों की वजह से परिवारों की स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। भाग के अधिकारी और प्रशासन भी परिवार जनों को उकसा रहे हैं जिसका नतीजा यह है कि कई जगहों से महिलाओं के साथ घरों में मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। परंतु महिलाएं मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की यंत्रणा को झेलते हुए अभूतपूर्व साहस के साथ आंदोलन में डटी हुई हैं।

हरियाणा के आंदोलनों के इतिहास में महिलाओं का यह आंदोलन ऐतिहासिक है। इससे पहले हरियाणा में परियोजना कर्मियों की इतनी लंबी हड़ताल कभी नहीं हुई। हरियाणा जैसे सामंती समाज में महिलाओं का इतना लंबा आंदोलन चलना अपने आप में एक मिसाल है।
राज्य में 52000 आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स कार्यरत हैं जिनमें से बड़ी संख्या विधवा महिलाओं की है। यह महिलाएं 0 से 6 साल के बच्चों गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी आहार प्रदान करने और स्वास्थ्य देखभाल करने के साथ-साथ महिलाओं व बच्चों से संबंधित सैकड़ों योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करती हैं। 45 साल से आंगनवाड़ी परियोजना में इतना महत्वपूर्ण काम करने के बावजूद भी इन महिलाओं को आज तक कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया और ना ही न्यूनतम वेतन दिया गया। राज्य में वर्कर को 11448 रुपए और हेल्पर को 6045 रूपए मानदेय मिलता है। साल 2018 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लंबे आंदोलन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में घोषणा की थी कि वर्कर को कुशल और हेल्पर को अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाएगा। इनके वेतन को भी महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा गया परंतु 2 महीने बाद ही सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। साल 2018 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आंगनवाड़ी वर्कर्स के वेतन में 1500 रुपए और हेल्पर के वेतन में 750 रूपए बढ़ोतरी की घोषणा की थी। राज्य सरकार इस पैसे को भी दबाए हुए बैठी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स में सरकार की इस वादाखिलाफी के खिलाफ भारी आक्रोश था जिसकी परिणीति यह आंदोलन है। यह आंदोलन सीटू से संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन तथा एआईटीयूसी से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन के तालमेल से बनी कमेटी के दिशा निर्देशन में चल रहा है। राज्य सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और बार-बार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स,हेल्पर्स कम्युनिस्ट नेताओं के बहकावे में ना आएं। 2018 में भी जब आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स का आंदोलन चला था तो मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा में कहा था कि यह लाल झंडे के लोग हैं इनकी बदमाशी नहीं चलने देंगे। हरियाणा में भाजपा सरकार को लगातार कम्युनिज्म का भूत सताता रहता

है। सरकार के इस प्रचार के बावजूद आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स मजबूती के साथ लाल झंडा थाम कर आंदोलन में डटी हुई हैं।

जनवादी महिला समिति की हरियाणा इकाई भी लगातार इस आंदोलन में सक्रिय सहयोग कर रही है। 10 जनवरी को संगठन द्वारा सभी जिलों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में प्रदर्शन किए गए और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजे गए। 14 फरवरी को करनाल में हुई राज्य स्तरीय रैली में संगठन ने भागीदारी की और 10000 रूपए का आर्थिक सहयोग भी आंदोलन को दिया। 22 व 23 फरवरी को सभी जिलों पर भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। संगठन की राज्य अध्यक्ष उषा सरोहा और जींद की कोषाध्यक्ष नूतन प्रकाश पर आंदोलन के चलते मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। जिला का नेतृत्व लगातार इस आंदोलन में भागीदारी कर रहा है और स्थानीय स्तर पर भी सहयोग जुटाने की कोशिशें की जा रही हैं।

पहले करोना महामारी वजह से लाभार्थियों को ताजा पौष्टिक भोजन ना मिलना और अब हड़ताल की वजह से पोषण संबंधी आहार बिल्कुल बंद हो जाने से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर भयंकर प्रभाव डाल सकता है। देश में पहले से ही कुपोषण बढ़ रहा है परंतु महिला हितैषी होने का पाखंड करने वाली राज्य की भाजपा सरकार को ना तो लाभार्थी महिलाओं की चिंता है और ना ही आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं की। आंगनवाड़ी में खाना बनाने वाली मदर ग्रुप की महिलाओं का काम भी 2 साल से छूटा हुआ है। आईसीडीएस जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को सरकार निजी हाथों में सौंपना चाहती है। नई शिक्षा नीति के नाम पर आईसीडीएस और प्राथमिक शिक्षा दोनों को तहस-नहस किया जा रहा है। यह आंदोलन इस महत्वपूर्ण मुद्दे को भी जनता के बीच में लेकर जा रहा है जिससे सरकार बुरी तरह से बौखलाई हुई है। परंतु बातचीत के रास्ते हल निकालने की बजाए आंदोलन को दबाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रही है। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स भी सिर पर कफन बांध कर लड़ रही हैं। निश्चित तौर पर जीत संघर्ष की होगी।

आओ प्यार करें

नलिन रंजन सिंह
(जलेस)

मैंने युद्ध और शांति में
शांति को चुना
मैंने मृत्यु और जीवन में
जीवन को चुना
वे जो भरा-पूरा जीवन जी कर चले गए
उनके शोक में डूबने की जगह
मैंने तुम्हारे साथ
प्रेम में डूबना चुना

चारों ओर के शोर से बचते हुए
मैंने प्रेम के क्षणों को जी लेना चाहा
जो हमारे और तुम्हारे
साथ होने से संभव थे
नफरत की तमाम आँधियों के बीच
हम बाहें थामें खड़े रहे
और प्रेम में डूबे रहे
यह नफरत की सबसे बड़ी पराजय थी

हमने माथे पर
तुम्हारे देश का झंडा लगाया
और अपने देश के हुक्मरानों से कहा
हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए
उनके तानाशाही फरमानों के बीच
हमारी आवाज
पूरी दुनिया में गूँजती रही
दुनिया के अरबों लोगों ने
शांति को चुना
प्यार को चुना

मैंने बहुत पहले तुमसे कहा था
छद्म अध्यात्मवादी
घटिया नशाखोर
युद्ध उन्मादी
नफरती जिहादी होने से अच्छा है
आओ प्यार करें।

बम पनाहगाह में जन्मी नन्ही बच्ची के लिए

मनजीत मानवी
(केंद्रीय कमेटी सदस्य, एडवा)

युद्ध और बमबारी के तमस के बीच
मौत की खौफ़नाक हवाओं से टकराती
यूक्रेन, कीव शहर की एक ज़मीदोज़ पनाहगाह में जन्मी
ऐ नन्ही मासूम अनजान बच्ची

तुम्हें निश्चित ही खुले आसमान के नीचे
स्वतंत्र, महफूज़ और साफ-सुथरी हवाओं में
किसी घर, चिकित्सालय या हस्पताल के आँगन में
आतुर माँ की नरम बाँहों में आना था

तुम्हें पूरा हक था इस धरा की दहलीज़ पर
शांत, स्थायी और खुशनुमा माहौल में
नवजात जीवन की पहली सांस लेने का
मगर ऐसा हो न सका

खेद है कि ऐसा हो न सका और
गोली बारूद व अनगिनत तोपों की
विषैली उद्दंड गंध से झुलसती
बंकर की खुरदरी भूमि ने किया तुम्हारा अभिनंदन

समस्त मानवजाति शर्मिंदा है ऐ नन्ही बच्ची
तुम्हें अपनी पहली सांस में ही
अपने नाज़ुक गले के भीतर गटकनी पड़ी
विध्वंस और नृशंसता की विषाक्त घुट्टी

अफ़सोस कि तबाही के इस अनावृत्त कथानक में
संशय और अनिश्चय की संकरी दीवारों में पल कर
तुम्हें स्वयं ही लिखनी होगी अब
यकीन, हिफ़ाजत और मुहब्बत की कथा

विनाश के मलबे से कुछ राख संभाले मुठ्ठी में
खुद ही गढ़ना होगा तुम्हें
अमन और शांति का वह नगमा
जिसे युद्ध की त्राहि के बीच गा सके ये दुनिया

हम पुनः संतापयुक्त हैं ऐ नन्ही बच्ची
कि इस समय लापता हैं पेड़ों से गौरैया और बुलबुल
हमारे पास तुम्हें देने के लिए फिलहाल झूला या लोरी नहीं
युद्ध के धधकते भोंपू और दिल में जलता धुआँ ही बचा है !